भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या: 317

गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2022/17 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की स्थापना

317. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नए ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना हेतु नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त उक्त प्रस्तावों और सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से ग्रीनफील्ड विमानपत्तन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (घ): भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित देशभर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना हेतु 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। देशभर में स्थित ये 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग और

शिरडी, कर्नाटक में कलबुर्गी, बीजापुर, हसन और शिमोगा, मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और हीरासर, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में डगदर्थी, भोगापुरम और ओर्वाकल (कुरनूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और दोन्यी पोलो तथा अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर हैं।

इनमें से, 9 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों अर्थातः दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पैकयोंग, कलबुर्गी, ओर्वाकल (कुरनूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर और दोन्यी पोलो, ईटानगर प्रचालनिक किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने तीन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों अर्थात राजस्थान में अलवर, मध्य प्रदेश में सिगरौली तथा हिमाचल प्रदेश में मंडी के निर्माण के लिए प्रथम चरण निकासी अर्थात साइट क्लियरेंस प्रदान कर दी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, हिमाचल प्रदेश में मंडी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजना को 2022 में 'साइट क्लियरेंस' प्रदान किया गया है।